भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 309

उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024

निर्बाध 3जी/4जी/5जी कनेक्शन

309. श्री डी.एम. कथीर आनंद:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दूरसंचार घनत्व बढ़ाने तथा इसके अंतर्गत आने वाले शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध 3जी/4जी/5जी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार बीएसएनएल जिस पर अभी भी उसके पूर्व उपभोक्ताओं द्वारा लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शनों को वापस करने के आधार पर 'प्रतिदाय' की अधिक राशि बकाया है, के कारण सरकार समस्याओं का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में कुल कितने उपभोक्ताओं ने बीएसएनएल की सेवाएं लेना बंद किया है; और

(घ) तमिलनाडु में बीएसएनएल के उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली सिग्नल और नेटवर्क संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु बीएसएनएल द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) एवं (घ) वेल्लोर जिले में 4,301 बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) 2जी/3जी/4जी/5जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं।

सरकार देश के सेवा से वंचित सभी गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के माध्यम से 4जी सेचुरेशन स्कीम सहित विभिन्न स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

4जी सेचुरेशन स्कीम के अंतर्गत बीएसएनएल ने वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 14 साइटों के लिए योजना बनाई है।

(ख) एवं (ग) लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड वापस करने वाले बीएसएनएल उपभोक्ताओं को बकाया राशि की कटौती करने के बाद उनकी राशि वापस की जा रही है। एफटीटीएच कन्वर्जन के मामले में रिफंड लागू नहीं होता। पिछले तीन वर्षों में बीएसएनएल ब्रॉडबैंड और एफटीटीएच सेवाएं डिस्कनेक्शन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**ब्रॉडबैंड**	**एफटीटीएच**
2021-22	33,56,639	3,94,512
2022-23	6,09,760	6,02,306
2023-24	11,23,005	7,83,781

*****